"लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री शो - 2024 के समापन समारोह के अवसर पर महामहिम राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया जी का अभिभाषण

दिनांक : 7 जनवरी 2024, रविवार	**समय : 3.20 PM**	**स्थान : खानापाड़ा, गुवाहाटी**

- असम विधान सभा के माननीय अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी जी,
- असम के माननीय कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा जी,
- माननीय वित्त मंत्री श्रीमती अजन्ता नेओग जी,
- पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के माननीय मंत्री श्री जयंत मल्ल बरुआ जी,
- माननीय वन मंत्री श्री चन्द्र मोहन पटोवारी जी,
- आसाम लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री मनोज सैकिया जी,
- अन्य विशिष्ट अतिथिगण,
- विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण,
- मीडिया के मेरे मित्रों,
- एवं उपस्थित देवियों और सज्जनों !

नमस्कार !

जैसा कि आप सब जानते हैं कि असम सरकार ने "लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री शो-2024" का यह भव्य आयोजन, हमारे किसान भाइयों और युवा उद्यमियों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया है। यह शो पिछले 5 जनवरी से ही चल रहा है। आज मुझे "लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री शो-2024" के इस समापन समारोह में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।

इस शो के माध्यम से, विशेष रूप से हमारे किसान भाइयों और युवा उद्यमियों को निश्चय ही प्रेरणा मिली होगी- यह मेरा विश्वास है। हालांकि इस आयोजन का उद्देश्य- हमारे किसानों और युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। यह शो उनके लिए और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें पशुधन और पोल्ट्री के लिए उपयोग की जाने वाली नई-नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाता है।

मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान पशुधन और पोल्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें पशुधन और पोल्ट्री की विभिन्न नस्लों के बारे में विविध जानकारियां साझा की गईं। मुझे लगता है कि उस सेमिनार से हमारे किसान और युवा उद्यमियों को कुछ न कुछ अवश्य ही लाभ मिला होगा।

मुझे यह जानकर और भी प्रसन्नता है कि पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में किसान भाइयों के साथ-साथ बड़ी संख्या में युवा उद्यमियों ने भी भाग लिया, जो कार्यक्रम की सार्थकता को दर्शाता है। इस अवसर पर मैं विभाग के माननीय मंत्री श्री अतुल बोरा और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, जिन्होंने रात-दिन मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है।

मित्रों,

असम का पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग एक पुराना विभाग है। इसकी स्थापना वर्ष 1905 में ही हुई थी। उस समय इस विभाग का नाम "सिविल वेटरनरी डिपार्टमेंट" (सीवीडी) था, जिसकी नींव ब्रिटिश अधिकारी विलियम हैरिस द्वारा रखी गई थी।

आजादी से पहले विभाग का उद्देश्य - घोड़े के प्रजनन, पशु रोग नियंत्रण और पशु चिकित्सा शिक्षा की देखभाल करना था। हालाँकि, अब समय बदल गया है और पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग (एएचवीडी) अब असम का एक प्रमुख विभाग है, जो पशुधन और मुर्गीपालन करने वाले किसानों भाइयों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए राज्य के पशु स्वास्थ्य, पशु कल्याण और पशुपालन गतिविधियों की देखरेख के लिए समर्पित है।

विभाग का मुख्य दृष्टिकोण- किसानों के जीवन-स्तर को बढ़ाना और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त यह विभाग पशुधन की सुरक्षा और पोल्ट्री की सतत वृद्धि के लिए भी काम कर रहा है, जो सराहनीय है।

बंधुओं,

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का योगदान 19.89 प्रतिशत है, जिसमें से केवल पशुधन और पोल्ट्री क्षेत्र का योगदान 5.30 प्रतिशत है। राज्य के अंदर दूध, मांस और अंडे की मांग को पूरा करने के लिए असम सरकार स्थानीय किसानों और युवाओं को हमेशा प्रोत्साहित करती आई है। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में अनेक नए स्टार्टअप खड़े हुए हैं और लोग धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

यह हम सब के लिए संतोष का विषय है कि वर्तमान में हमारा असम "पिग प्रोडक्शन" (सुअर उत्पादन) के क्षेत्र में देश भर में नम्बर वन पर है और ब्रॉयलर उत्पादन में भी आत्मनिर्भर है। दूध और अंडे के मामले में हमारा राज्य राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है। इसलिए असम सरकार ने "नॉर्थ ईस्ट डेयरी एंड फूड्स लिमिटेड" की शुरुआत की है। यह सरकार द्वारा बनाई गई एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।

असम डेयरी विकास योजना के तहत राज्य में प्रति दिन 10 लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए असंगठित डेयरी क्षेत्र को एक संगठित दायरे में लाने की जरूरत होगी। राज्य में दूध के स्थायी विपणन को सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर बनाना होगा और किसानों को उसमें जोडऩा होगा। तभी जाकर हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं।

मुझे खुशी है कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिए, मेरी राज्य सरकार केंद्र प्रायोजित सभी योजनाओं को लागू कर रही हैं। जिसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (LH और DC) कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) आदि प्रमुख हैं। इसके लिए किसानों और उद्यमियों को वित्तीय सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

आर्थिक महत्व के पशु-रोगों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेला और क्लासिकल स्वाइन बुखार के लिए नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही टीका लगाए गए पशुओं को विशिष्ट पहचान संख्या के साथ टैग किया जाता है और कार्यक्रम की निगरानी के लिए डेटा को एक केंद्रीकृत पोर्टल में दर्ज किया जा रहा है।

मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से डोर स्टेप सेवा वितरण तंत्र शुरू किया गया है और राज्य में 181 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां कार्यरत हैं और किसान 1962 टोल फ्री नंबर डायल करके घर पर ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

मानव संसाधन के बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। इसलिए विभाग के सभी रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता है और इसके लिए मेरी सरकार रिक्त पदों की भर्ती के लिए निरंतर काम कर रही है।

राज्य के स्वामित्व वाली योजनाओं में "असम दूध, मांस और अंडा मिशन" मुख्यमंत्री समग्र ग्राम उन्नयन योजना, (सीएमएसजीयूवाई) के प्रमुख घटकों में से एक है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है।

ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि (आरआईडीएफ) की सहायता से बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास हो रहा है। पशुधन के उन्नत चिकित्सा हेतु अस्पतालों और औषधालयों, उपकेंद्रों और विभिन्न कार्यालयों का पुनर्निर्माण चल रहा है।

आप सभी जानते हैं कि राज्य में लगभग 27.50 लाख किसान परिवार हैं और लगभग सभी परिवारों के पास पारंपरिक रूप से पशुधन है और कई किसान व्यावसायिक रूप से पशुपालन कर रहे हैं।

राज्य में पशुपालन क्षेत्र का व्यावसायीकरण जोर पकड़ रहा है। राज्य की आबादी के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन के लिए शिक्षित युवाओं की भागीदारी के साथ राज्य में बड़ी संख्या में वाणिज्यिक सुअर, मुर्गीपालन और डेयरी फार्म खुल रहे हैं।

मुझे आपको यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि "Assam Veterinary and Livestock Mission (AVLM)" के माध्यम से राज्य सरकार "पशुधन और पशु चिकित्सा" क्षेत्र के पुनर्गठन पर भी विचार कर रही है। इसमें सेवा वितरण प्रणाली के चार स्तंभ शामिल हैं; बुनियादी ढाँचा, रसद, दवाएँ और मानव संसाधन।

प्रत्येक जिले में 35 मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा डिब्रूगढ़, बोकाखाट और गुवाहाटी में 3 पेट हॉस्पिटल की स्थापना के लिए नई पहल कार्यान्वयन के अधीन है। आने वाले दिनों में राज्य के कृषक समुदाय को निश्चय ही इससे लाभ मिलने वाला है।

राज्य के पारंपरिक उत्पादन को बढ़ावा देने और वाणिज्यिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं कृषक समुदाय से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह करता हूं, ताकि क्षेत्र में विकास में स्थिरता सुनिश्चित की जा सके और राज्य की अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय विकास के अनुरूप बढ़े।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि "लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री शो - 2024" के माध्यम से राज्य के अनेक युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें प्रेरणा मिलेगी और वे इस नए उद्यम को अपनाकर "आत्मनिर्भर भारत" के मिशन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

अंत में, मैं आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया और मुझे दो शब्द रखने का मौका दिया। आप सभी को एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय हिन्द।